विचार बिन्दु

नम्रता तन की शक्ति, जीतने की कला और शौर्य की पराकाष्ठा है। –विनोबा

युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए

भारत विश्व का सबसे युवा देश है और यहां पर युवाओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। इसी युवा शक्ति का गुणगान करते हुए देश के सभी नेता गण सदैव यह कहते रहे हैं कि इसी के बल पर देश तेजी से प्रगति करेगा और विश्व गुरु का अपना पुराना स्थान प्राप्त करेगा। यह बात सही भी है कि युवाओं के पास अथाह ऊर्जा होती है और यदि उन्हें सही दिशा में लगाया जाए तो वे देश को तीव्र गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं।

देश में सरकारें, केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार, उनके साथ जैसा बर्ताव कर रही हैं, वह शनैः शनैः युवाओं को देश के लिए उपयोगी ताकत के स्थान पर ऐसे आक्रोशित समूह के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं जो दिशाहीन है।

आइए, समझने का प्रयास करें कि युवाओं में आक्रोश बढ़ने का कारण क्या है?

सबसे पहले तो युवाओं को अच्छी पढ़ाई की आवश्यकता होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवा, आसानी से तकनीकी क्षेत्र में अथवा अन्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अपने घर के युवाओं को उच्च शिक्षण संस्थान में भेजने के लिए कई बार माता पिता को अपनी खेती की भूमि गिरवी रखनी पड़ती है, अथवा संपत्ति बेचने होती है। इतना खर्चा करने के पश्चात जब युवा शिक्षण संस्थानों से निकलता है तो उसकी आशा होती है कि वह अच्छी कमाई करे ताकि वह गरिमामय जीवनयापन करने योग्य बन सके।

वह एवं उसके माता-पिता आशा करते हैं कि वह अब व्यवस्थित रूप से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में गत वर्षों में निजीकरण को बढ़ावा देने के कारण, फीस में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कई बार उसे इस राशि की व्यवस्था कर्जा लेकर करनी होती है। वह यह सोच कर ऐसा करता है कि सम्भवतः अच्छा रोजगार प्राप्त होने पर वह इसे चुका पाएगा।

सरकारी नौकरी के लिए देश भर में करोड़ों आवेदन प्राप्त होते हैं। सरकारी नौकरी की तलाश में युवा अपने जीवन के कई बहुमूल्य वर्ष बिता देते हैं, क्योंकि अधिकांश भर्ती प्रक्रियाएं पेपर लीक होने या अन्य कारणों से न्यायिक प्रक्रिया में उलझने के कारण पांच से सात वर्षों तक अटकी रहती हैं।

सरकार हालांकि बार-बार यह कहती रही है युवाओं को नौकरी देने वाला बनना चाहिए ना कि नौकरी की तलाश करने वाला। यह सीख सही भी है, किंतु जिस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था देश में है, उसे पूरी करने के बाद यदि वह कोई अच्छा व्यवसाय प्रारंभ करने लायक नहीं बन सकता है या उसमें कोई हुनर विकसित नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी युवाओं पर डालना उचित नहीं होगा। यदि सरकार शिक्षा व्यवस्था में उपयुक्त परिवर्तन करने में सफल नहीं हुई, तो इसमें युवाओं का क्या दोष है?

राजस्थान की शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) में लगभग 16 लाख परीक्षार्थी बैठे। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के समाचार परीक्षा के दिन ही प्राप्त होने लगे थे। पुलिस द्वारा गठित विशेष ऑपरेशन ग्रुप कई दिनों की जांच के पश्चात इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। अर्थात परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र बाहर आ चुका था। शायद यही कारण था कि कुछ विद्यार्थियों को 150 में से 146 अंक तक प्राप्त हुए। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इतने अधिक अंक प्राप्त होना लगभग असंभव है। स्पष्ट है, जब प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले पता हो, तब ही, इतने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। बेरोजगार शिक्षित युवा वर्षों तक इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कोचिंग में हजारों रुपए खर्च करते हैं और उसके बाद अपनी योग्यता अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त नहीं कर पाए, तो उनका ठगे हुए महसूस करना स्वाभाविक है।

जब पेपर लीक होने का संदेह उत्पन्न हो गया तो तत्काल ही इस परीक्षा को निरस्त कर दोबारा परीक्षा करानी चाहिए थी ।ऐसा ना करके, उसने योग्य विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय किया है। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि लाखों-करोड़ों रुपए के लेनदेन से प्रश्न पत्र लीक कराया गया एवं उसे हजारों व्यक्तियों तक परीक्षा से पूर्व ही पहुंचा दिया गया ।यह संभव नहीं है कि उच्च स्तर पर संरक्षण के बिना इस प्रकार प्रश्न पत्र लीक हो जाए। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक किसी भी उच्च स्तर के अधिकारी को इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया गया है। सरकार को यह चाहिए कि वह परीक्षा निरस्त करके पूरा प्रकरण सी बी आई को सौंप दे।

अब भी सरकार के पास समय है कि वह युवाओं से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करे। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को निष्पक्ष रूप से संवेदनशीलता अपनाते हुए दिखलाये। सरकारें भर्ती, केवल और केवल योग्यता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। परीक्षा संचालन का काम ऐसे लोगों को सौंपा जाए जिनकी ईमानदारी संदेह से परे हो।

भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि परीक्षा की निष्पक्षता एवं पवित्रता बनी रहे। प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्रश्नों का क्रम अलग हो सकता है जिससे सामुहिक नकल नहीं हो सके। इसी प्रकार, प्रश्न ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनका उत्तर किताब देखकर भी आसानी से देना सम्भव न हो। प्रश्न पत्र एक घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर भेजा जाय तो लीक होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। इस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसा किया भी था।

तकनीकी विकास के कारण ऐसा करना सम्भव हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था। वहां की सरकार ने परीक्षा को निरस्त किया, कई लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल में डाला एवं उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट भी किया।

इस लीक हुए प्रश्न पत्र के प्राप्तांक के आधार पर परीक्षार्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया भी शिक्षा विभाग ने प्रारंभ कर दी है। विवाद में आए बोर्ड अध्यक्ष को विलंब से ही सही, सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष की कार्य प्रणाली प्रारंभ से ही संदेह के घेरे में रही है। उन्होंने एक निजी महाविद्यालय के कर्मचारी को परीक्षा के प्रश्न पत्र से संबंधित गोपनीय कार्य में क्यों लगाया? लाखों परीक्षार्थियों के, जो दो-तीन साल व्यर्थ हुए, उसकी भरपाई कोई भी किस प्रकार कर सकेगा?

इसी प्रकार की स्थिति हाल ही में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) द्वारा विभिन्न पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के संबंध में उत्पन्न हुई है। लगभग डेढ़ करोड़ परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस परीक्षा के लिए जो विज्ञापन निकाला उसके साथ जो नोटिस जारी हुआ वह 70 से भी अधिक पृष्ठों का था ।इतना विस्तृत और जटिल दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के लिए समझना संभव नहीं है। क्या रेलवे बेरोजगारों के लिए कोई सरल भाषा में संक्षिप्त विज्ञप्त नहीं जारी कर सकती थी? न केवल यह, विज्ञापन जारी होने के पश्चात, परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता में भी बदलाव किया। परिणाम घोषित करने के बाद यह आरोप भी लग रहा है कि जितने लोगों को सफल घोषित किया जाना चाहिए था उनमें से 50 प्रतिशत को भी नहीं किया गया। इसी प्रकार पहले एक ही स्तर की परीक्षा होनी थी जिसे दो स्तर की परीक्षा बना दिया गया। क्या यह बेरोजगार छात्रों के साथ मजाक नहीं है कि वह जिस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी शर्तों में समय-समय पर इस प्रकार के बदलाव किए जाएं कि अनिश्चितता और बढ़ जाए?

इसी प्रकार के कुछ अन्य विवादों के फल स्वरुप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई है। जो बेरोजगार ,वर्षों से तैयारी कर रहे थे, अब निराश एवं असंतुष्ट होकर सड़कों पर उतर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। यदि कोचिंग संस्थान के संचालकों में से किसी ने रेलवे के निर्णय मे हुई अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कोई ट्वीट किया और उसे लगभग 80 लाख परीक्षार्थियों ने पुनः ट्वीट किया तो इसे एफ.आई.आर. का आधार क्यों माना जा रहा है? गांधी के देश में, जहां अन्याय के विरुद्ध सत्याठाह को अत्यावश्यक अंग माना गया, वहीं ऐसा करने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उसे किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है।

जिन व्यक्तियों द्वारा समस्या उत्पन्न की गई उनके विरुद्ध कार्रवाई ना करके जो पीड़ित बेरोजगार युवा हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। खान सर जैसे प्रसिद्ध शिक्षक जो इन परीक्षार्थियों के साथ खड़े हैं, उन्हीं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। आंदोलनरत बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर बुरी तरह पीटा। बेरोजगार युवकों ने भी आक्रोश में भरकर रेलवे ट्रैक पर आकर रेलों आवागमन बंद कर दिया। इन्हीं में सम्मिलित कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रेलवे की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया, जिसे किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। रेलवे ने एक विज्ञप्त के द्वारा भविष्य में रेलवे में किसी भी प्रकार की भर्ती के लिए ऐसे छात्रों को अपात्र माना है जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं। कार्रवाई करनी किसके विरुद्ध थी और की किसके विरुद्ध जा रही है?

ऐसा लगता है जैसे सभी सरकारें युवाओं के सब्र की परीक्षा ले रही है। सरकारों को यह समझना होगा कि जब बेरोजगारी चरम पर हो तो युवाओं के सब्र का बांध कभी न कभी टूट ही जाएगा।

सरकारों को व्यवस्था में सुधार करना होगा। एक ओर विभिन्न विभागों में लाखों पद रिक्त है वहीं दूसरी ओर लाखों-करोड़ों योग्य युवा बेरोजगार हैं। समय की मांग है कि सरकारों में नियुक्तियां समय पर निष्पक्ष रूप से एवं संदेह से परे की जायें। सरकार यह सलाह देना बंद करें कि युवा सरकारी नौकरी के स्थान पर अपना स्वरोजगार क्यों नहीं कर लेते? यह स्थिति तब बनेगी, जब शिक्षा पद्धति ऐसे युवा तैयार करेगी जो किसी न कौशल में दक्ष हों। कोई नहीं चाहता कि अपने जीवन को दांव पर लगाकर किसी प्रकार का कोई आंदोलन सरकार के विरुद्ध करे, किंतु जब सरकार संवेदनहीनता की हदें पार करेगी तो हम, वर्षों से बेरोजगार युवाओं से क्या अपेक्षा कर सकते हैं?

अब भी सरकार के पास समय है कि वह युवाओं से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को निष्पक्ष रुप से संवेदनशीलता अपनाते हुए दिखलायें। सरकारें भर्ती, केवल और केवल योग्यता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। परीक्षा संचालन का काम ऐसे लोगों को सौंपा जाए जिनकी ईमानदारी संदेह से परे हो। जो व्यक्ति परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की अनियमितता में लिप्त पाए जाएं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए चाहे। वह किसी भी स्तर का अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि क्यों ना हो ,एक बार कठोरतम कार्रवाई का संदेश लोगों में चला जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करें। सरकार रिक्त पदों हेतु समयबद्ध कार्यक्रम जारी करे एवं यह सुनिश्चित करे कि विज्ञप्त और नियुक्ति में अन्तर एक वर्ष से अधिक न हो। यदि सरकारों ने अब भी युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो युवा वर्ग का आक्रोश लावा बनकर कब फ़ूट पड़ेगा, कह नहीं सकते।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

चुनावों में मुफ्त उपहार लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं

बाल मुकुंद ओझा

चुनावों के दौरान सरकारी कोष से जनधन को लुटाने के मामले देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गए है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में मुफ्त की बारिश हो रही है। राजनैतिक पार्टियों द्वारा मत हासिल करने के लिए राजकीय कोष से मुफ्त सुविधाएं देने का प्रकरण सियासी हलकों में गर्माने लगा है। देश के बुद्धिजीवि जमात का मानना है इससे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हिलने लगी है। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, 'यह एक गंभीर मुद्दा है और मुफ्त वितरण का बजट नियमित बजट से अलग होता है। भले ही यह भ्रष्ट काम नहीं है, लेकिन यह मैदान में असमानता तैयार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजे नोटिस के मुताबिक केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को तय करना है कि जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान जनता के पैसे से यानी पब्लिक फंड से मुफ्त घोषणाएं करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर गाइडलाइंस तय हों। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक जनहित याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने और उनके चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की गई है, जो मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं देने के वादे कर रहे हैं।

इस याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए पब्लिक फंड से चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार देने का वादा करने या मुफ्त उपहार बांटना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। इससे चुनाव प्रक्रिया प्रदूषित होती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे चुनाव मैदान में एक समान अवसर के सिद्धांत प्रभावित होते हैं। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है, कि अब वह समय दूर नहीं, जब एक राजनीतिक दल कहेगा कि 'हम आपके आवास में आपके लिए खाना बनाएंगे'। जबकि, दूसरा यह कहेगा कि 'हम न केवल खाना बनाएंगे, बल्कि आपको खिलाएंगे भी।' देखा गया है चुनावों में सभी दल लोकलुभावन वादों के जरिए दूसरे दलों से आगे निकलने की जुगत में हैं। आम आदमी पार्टी मुफ्त सुविधाएं देने के वादों में सबसे आगे है। यह पार्टी मतदाताओं को मुफ्त बिजली पानी आदि लुभावनी घोषणाएं कर दिल्ली में सत्ता हासिल कर चुकी है। आप ने पंजाब में सत्ता में आने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। कुछ अन्य राज्यों के चुनावों में भी इसी तरह की घोषणाएं की गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। उन्होंने सभी घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। कांग्रेस ने यूपी में लड़कियों के लिए स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन में वृद्धि, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। याचिका दाखिल करने वाले एक वकील अश्विनी उपाध्याय ने पंजाब के संदर्भ में कहा कि आम आदमी पार्टी के राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए प्रति माह 12,000 करोड़ रुपये की जरूरत है, शिरोमणि अकाली दल के सत्ता में आने पर प्रति माह 25,000 करोड़ रुपये और कांग्रेस के सत्ता में आने पर 30,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। जबकि सच्चाई यह है कि राज्य में जीएसटी संग्रह केवल 1400 करोड़ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सच्चाई यह है कि कर्ज चुकाने के बाद पंजाब सरकार कर्मचारियों- अधिकारियों के वेतन-पेंशन भी नहीं दे पा रही है तो ऐसे में वह मुफ्त उपहार देने का वादा कैसे पूरा करेगी? याचिकाकर्ता का कहना है कि कड़वा सच यह है कि पंजाब का कर्ज हर साल बढ़ता जा रहा है। राज्य का बकाया कर्ज बढ़कर 77,000 करोड़ रुपये हो गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजस्व प्राप्ति की तुलना में सरकार का खर्च 90,730 करोड़ रुपये ज्यादा है। पिछले साल यह घाटा 80,850 करोड़ रुपये रहा था। घाटा हर साल बढ़ रहा है। सरकार द्वारा भरे जाने वाले ब्याज का स्तर 82,400 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। अगर उत्तर प्रदेश में खर्च का आकलन करें, तो वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर कुल खर्च 2.56 लाख करोड़ रुपये है। यह राज्य के कुल बजट के करीब आधे के बराबर है। बताते हैं चुनावी लोकतंत्र में मुफ्त उपहार की परंपरा तमिलनाडु से शुरू हुई थी। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक की नेत्री जय ललिता ने मुफ्त उपहार बांट कर द्रमुक से सत्ता छीनी थी। वहां पहले मोबाइल, टीवी सेट, डिनर सेट, हैदराबादी मोती के सेट बंट चुके हैं। पिछले अनेक चुनावों में मुफ्त उपहार और सुविधाएं देने की एक परंपरा सी पड़ गई। मतदाता भी ऐसी घोषणाओं का इंतज़ार करते हैं जो किसी भी स्थिति में लोकतंत्र के हितकारी नहीं कहा जा सकता।

–बाल मुकुंद ओझा
(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार)

महानता के मायाजाल का यथार्थ!

डॉ रामावतार शर्मा

लोगों में सदा से एक बात देखी गई है कि वे एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश में रहते हैं जिस पर वे मुग्ध हो सकें, उसको पूजनीय मान सके, देवतुल्य समझ सकें। अब यही व्यक्ति देश नायक होगा, धर्म रक्षक होगा, संस्कृति संरक्षक होगा, युग पथप्रदर्शक होगा और न जाने क्या क्या होगा! इस व्यक्ति में कोई मानवीय कमजोरियां नहीं होती हैं, उसका हर निर्णय सत्य और देशहित पर आधारित होता है इसलिए उसे सवालों के घेरे से बाहर होना चाहिए। दबी से दबी जबान में भी उठते सवालों को कुचलना ऐसे व्यक्तित्वों के प्रशंसकों को अपना एकमात्र जीवनोदेश्य लगने लगता है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यह इस लेख के बाहर का विषय है पर आज के भारत के एक बड़े मानस पटल पर छाए बीते समय के बड़े बड़े धार्मिक और राजनीतिक नायकों के भारत में दिए गए भाषणों की तुलना उनके यूरोप या अमेरिका में दिए गए भाषणों से की जाए तो एक बार तो पाठक सिर पीटने को मजबूर हो सकता है।

बात 1975 की है जब स्पेन के तानाशाह फ्रैंको की मृत्यु हुई और शासन पूर्व राजशाही के वारिस जुआनकार्लोस के हाथों आ गया जो कि यदि चाहता तो तानाशाह बन सकता था पर चालाक सम्राट समझ गया कि तानाशाही अब चलने वाली नहीं है तो उसने सांकेतिक राजशाही के साथ गणतंत्र की घोषणा कर देवतुल्य स्थान प्राप्त कर लिया। जनता उसको पूजती रही, जुआनकार्लोस सऊदी अरब तथा अन्य देशों से कमीशन में सैंकड़ों करोड़ यूरो कमा कर अय्याशियां करता रहा, प्रशंसक उन अय्याशियों पर पर्दा डालते रहे पर एक दिन वह राजपाट सब त्याग कर, बड़ी रकम की हेराफेरी कर 80 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष की महिला मित्र के साथ आबूधाबी जा बसा। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के एक वर्ग में जबरदस्त पकड़ थी पर उसी वजह से वह एक थोथा चना बन कर इतिहास में गुम हो गया। जयललिता भी काफी पूजी गई पर उन्होंने ज्यादा समय तो चप्पल, साड़ी तथा अन्य व्यक्तिगत सामान खरीदने में बिताया। महज जनधन के जोर से अम्मा की रसोई चलाना युग परिवर्तन नहीं होता है। आंध्र प्रदेश में एनटीरामाराव को लेकर कितनी दीवानगी हुआ करती थी! आज कोई ढूंढे तो भी उस मनुष्य का उस प्रदेश को कोई बड़ा योगदान नहीं नजर आएगा।

जब इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो हटी, पर हटी बहुत धीमी रफ्तार से और जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि जबरदस्त विकास होगा और अच्छे दिन आयेंगे तो माना कि विकास हुआ, पर हुआ उसी धीमी गति से जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ। जहां तक अच्छे दिनों की बात है तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा, अपने अपने मापदंड पर मुझे तो कवि दुष्यंत की पंक्तियां याद आ जाती हैं–

मत कहो आकाश में कोहरा घना है
यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।

जो तथाकथित बड़े लोग होते हैं वे समय के साथ साथ अति विशिष्ट लोग होते जाते हैं। वे लोग वर्षों वर्ष धन, सत्ता और साधनों के मायाजाल में घिर कर सामान्य नागरिकों के जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए वे तरह तरह के उन्मादों को प्रेरित करते रहते हैं। उनके चारों तरफ सुविधाभोगी नौकरशाही और स्वार्थ में लिप्त धनिक जमात एक घेरा बना लेती है जिसको सामान्य जन की वेदना भेदनही सकती, वरना क्या कारण है कि आज तक किसी भी सरकार ने पुलिस, प्रशासनिक और न्यायिक भ्रष्टाचार पर हाथ नहीं डाला? एक सामान्य नागरिक के जीवन में यदि इन तीन विभागों में सबकुछ समयानुसार और कानून सम्मत होता रहे तो अच्छे दिन चारों तरफ मौजूद हैं। पर ना नौ मन तेल होगा और न.....

–डॉ. रामावतार शर्मा,
(चिकित्सक एवं लेखक)

जयकारों से गूंजा मेहंदीपुर बालाजी का पावन धाम

सिद्धपीठ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में सोमवार को बालाजी महाराज का मंदिर आम भक्तों के दर्शनों के लिये खोल दिया गया।

मेहंदीपुर बालाजी, (निसं)। सिद्धपीठ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में सोमवार को बालाजी महाराज का मंदिर आम भक्तों के दर्शनों के लिये खोल दिया गया। सुबह महंत नरेशपुरी महराज के सानिध्य में प्रतिदिन की तरह सोमवार को बालाजी महाराज की पूजा-अर्चना व हवन किया गया। आरती के बाद सुबह 7:00 बजे से दर्शनों के लिए मंदिर के पट खोल दिये।

■ **21 दिन बाद बालाजी महाराज के दर्शन हुए**

इस दौरान स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं का 21 दिन बाद बालाजी महाराज के दर्शन हुए। वहीं कस्बे के बाजारों में श्रद्धालुओं की चहल-पहल नजर आने से स्थानीय व्यापार मंडल के चेहरे पर रौनक नजर आई। साथ ही सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर मास्क लगा कर बैठे नजर आए। इधर मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए सुरक्षा बंदोबस्त से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुविधा रही। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले वाहनों को कस्बे में प्रवेश नहीं दिया गया और डबल डोज के प्रमाण पत्र साथ लाने वाले श्रद्धालुओं को ही आस्था धाम में प्रवेश दिया गया।

सांभर में कक्षा नवीं के बाद हिन्दी माध्यम का नहीं कोई भी सरकारी स्कूल

सांभरझील, (निसं)। प्रदेश सरकार की ओर से हिन्दी माध्यम की सरकारी स्कूलों को भले ही इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सहूलियत दी हो, लेकिन अब यहां के सैंकड़ों अभिभावकों के सामने अपने बच्चों को कक्षा नौ के बाद हिन्दी माध्यम से पढ़ाने के लिये संकट खड़ा हो गया है।

इसके पीछे कारण सबसे बड़ा यह है कि यहां के राजनेताओं ने सरकार की ओर से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की प्रशंसा तो खूब की लेकिन वे शायद यह भूल गये जो बच्चे हिन्दी माध्यम से ही अपनी शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिये सांभर में अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है, लिहाजा गरीब तबके से लेकर मीडियम क्लास तक के अभिभावक यहां से तीन से चार किलोमीटर दूर बरडोटी, तेजा का बास, नोरंगुपरा में जाने की मजबूरी बनी हुई है। बताया गया कि ऐसे लोग सामूहिक रूप से निजी टैम्पो अथवा अन्य साधनों से जाकर आर्थिक बोझ भी उठा रहे हैं, जो उनके लिये प्रतिदिन जोखिम भरा भी सिद्ध हो सकता है। जानकारी में आया है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का भी इस दिशा में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री तक प्रभावी व ठोस पहल करने में कोई रूचि नहीं है, जिसके चलते इस महत्वपूर्ण ज्वलन्त समस्या का आने वाले निकट भविष्य में भी कोई समाधान होता दिखायी नहीं दे रहा है।

यहां के गरीब तबके के अभिवावकों के पास न तो इतना धन है और न ही बल जिसके दम पर वे खुद इस मामले को सरकार तक पहुंचाने में सफल हो सके। एक तरफ अंग्रेजी माध्यम से सरकारी स्कूल में पढ़ाई की खुशी तो मिली लेकिन हिन्दी माध्यम से सरकारी स्कूल का नहीं होना दुखद विषय बन चुका है। बताया जा रहा है कि एक दफा औपचारिकता करने के लिये यहां के कुछ लोगों ने सत्ता पक्ष से जुड़े फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के नेता पूर्व सांसद स्वर्गीय हरिसिंह के पुत्र जो कि खुद पिछली दफा यहां से विधानसभा का चुनाव लड चुके हैं के माध्यम से शिक्षा मंत्री रहे गोविन्द सिंह डोटासरा के समक्ष पुरानी धानमण्डी स्थित सराय स्कूल को क्रमोन्नत करवाने व रेलवे स्टेशन रोड स्थित संस्कृत विद्यालय में जहां पर्याप्त संख्या में कक्षा-कक्षों व लम्बे-चौड़े मैदान की उपलब्धता है में हिन्दी माध्यम स्कूल खोले जाने का अभ्यावेदन पर भी कोई सुनवायी नहीं होना ऐसे अभिभावकों व बच्चों के लिये मानसिक पीड़ादायक बना हुआ है। आरएमजीबी के पूर्व प्रबन्धक आलौक जौहरी ने बताया कि जब तक सरकार स्कूल क्रमोन्नत व नया स्कूल खोलने की स्थिति में नहीं है तो फिलहाल राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दो शिफ्टों में चलाने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि ऐसे सैंकडों बच्चे जो आगे चलकर देश का भविष्य बन सकते हे उनको हिन्दी माध्यम से पढायी करने का मौका मिल सके।

राशिफल मंगलवार 1 फरवरी, 2022

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास कृष्ण पक्ष, अमावस्या, मंगलवार, विक्रम संवत 2078, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सायं 7:44 तक, वारियान योग रात्रि 3:09 तक, बव करण दिन 11:16 तक, चन्द्रमा बुधवार प्रातः 6:45 पर कुमभ राशि में प्रवेश करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मकर, मंगल-धनु, बुध-मकर, गुरू-कुम्भ, शुक्र-धनु, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में।

कुमार योग दिन 11:16 से रात्रि 7:44 तक है। आज देवपितृकार्य अमावस्या, मौनी भौमवती अमावस्या, व्यतिपात पुण्य है। आज मेला हरिद्वार और प्रयागराज, अरोदय योग सूर्योदय से 11:16 तक है और द्वापर युगादि है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:18 से 11:19 तक, लाभ-अमृत 11:40 से 2:01 तक, शुभ 3:22 से 4:43 तक।

राहूकालः 8:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:17, सूर्यास्त 6:04

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

सिंह
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा।

धनु
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

वृष
व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

मकर
मनःस्थिति में सुधार होगा। मानसिक तनाव दूर होगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

तुला
परिवार में महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ
व्यक्तिगत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च होगा।

कर्क
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।